[श्री गोरे]

कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इस सभा को उसका भार उठाना होगा। हम भार उठाने के लिए तैयार हैं पर हमें यह तो बताया जाये कि क्या और कितना भार हमें उठाना होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री गोरे के स्थगन प्रस्ताव में सुबनसिरी तथा कामेंग डिवीजन का जिक्र है। स्थगन प्रस्ताव में कहा गया है कि नेपाल व लद्दाख में चीनी सेनायें सीमा पार करके घुस रही हैं। श्री वाजपेयी के स्थगन प्रस्ताव में नेफ़ा क्षेत्र में सीमावर्ती भारतीय सेना व चीनी सेना के बीच गोली चलने की घटना का उल्लेख है और अन्त में श्री कामले के प्रस्ताव में भारत सरकार की किसी नीति का न होना तथा संसद् को विश्वास में न लेना आदि का जिक्र है।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने उस समाचार का खण्डन कर दिया है। नाथूला दर्रे के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने कहा कि यह दर्रा वहां नहीं है। समाचार पत्र में भी यह नहीं कहा गया है कि यह दर्रा वहां है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं जानता हूं कि इस सभा के सदस्य देश के सीमान्त क्षेत्रों की इस परिस्थिति के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से स्थगन प्रस्तावों के बारे में कुछ कहना बड़ा कठिन होता है क्योंकि ये प्रस्ताव जगहों और इलाकों के ग़लत नामों पर आधारित रहते हैं। इसलिये उनके बारे में कुछ कहने में बड़ी मुश्किल पड़ती है। इसलिये मैं इन प्रस्तावों के बारे में अलग-अलग नहीं कहूंगा। मैं आवश्यक जानकारी देने की कोशिश करूंगा।

श्री हेम बरुआ का प्रस्ताव बड़ा ही बेतरतीब किस्म का प्रस्ताव है। उस में एक जगह कहीं की और दूसरी जगह कहीं और की ली गई है। वहां होने वाली घटनाओं वगैरह से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने अपनी जानकारी किसी अखबार से हासिल की है (अन्तरबाधा)।

पिछले-दो-तीन साल के दौरान में बहुत बार-बार तो नहीं, लेकिन हां कभी कभी चीनी सेनाओं ने, या उसकी कुछ टुकड़ियों ने हमारे सीमान्त क्षेत्रों में छोटे-मोटे तौर पर दखल जरूर दिया है, हमारे इलाकों में कुछ छोटी मोटी टुकड़ियां घुस आई हैं। वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच कोई साफ सीमा मौजूद नहीं है और इसलिये दोनों तरफ के लोग कभी-कभी एक-दूसरे की सीमाओं में पहुंच सकते हैं। हम ने १९५७-५८ में चीन सरकार का ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया था और उन्होंने अपनी टुकड़ियां वापस बुला ली थीं। और मामला वहीं खत्म हो गया था।

हां एक बार इससे कुछ ज्यादा गम्भीर घटना हो गई थी। मैं ने उसके बारे में यहां कहा भी था। पिछले साल लद्दाख में चीनियों ने हमारी पुलिस के एक छोटे दल को हिरासत में ले लिया था। उस के बारे में अभी भी लिखापढ़ी चल रही है; कोई फैसला नहीं हुआ है। अब इस साल जून में चीन की सरकार ने हम से शिकायत की कि हमारे मुल्क की फौजों ने चीनी इलाके पर गोलाबारी की थी और सीमा के अन्दर घुसकर मिग्यितुन नामक एक स्थान पर और तिब्बत-नेफा की सीमा के एक दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया था। चीन सरकार ने हम पर आरोप लगाया था कि हमारी फौजों ने तिब्बत के बाग़ियों की फौजों, या उनके शब्दों में 'लुटेरों' के साथ साठ-गांठ की है और चीन की जनवादी सरकार के खिलाफ़ गैर-कानूनी कार्यवाहियां की हैं। हम ने उसका जवाब दे दिया कि उनके इस आरोप में कोई भी सचाई नहीं है, और हम ने इस पर ताअ़जुब जाहिर किया कि चीन की सरकार ऐसे ग़लत ढंग के आरोपों को भी महत्व देती है। उसमें और कुछ नहीं हुआ था। हमारी फौजें जहां थीं, वहीं रहीं, हां सीमा के बारे में विवाद बना रहा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं दो बातें खास तौर पर कहना चाहता हूं । उन में से एक की अहमियत तो काफी ज्यादा है और वह आज की चीज़ भी है । उसके बारे में मैं बाद में कहूंगा । उन में से पहली यह है कि ७ अगस्त को चीनी फौजों के करीब २०० जवानों के एक दस्ते ने कामेंग फ्रंटियर डिवीज़न में चुथंगमु के उत्तर में खिन्जेमाने स्थान पर हमारी सीमा का उल्लंघन किया था । हम ने जब उन से वापस जाने के लिये कहा तो उन्होंने चौकसी करने वाली हमारी उस बहुत ही छोटी टुकड़ी पर हमला करके उसे ड्रोंकुंग साम्बा के पुल तक पीछे ढकेल दिया । हमारी टुकड़ी में कुल दस या बारह पुलिस मैन थे और चीन के फौजी उन से दस गुने, दो सौ थे । उन्होंने हमारे सिपाहियों को एक तरह से बिलकुल ढकेल कर पुल तक हटा दिया । गोली नहीं चली थी । बाद में चीन का फौजी दस्ता वापस चला गया और हमारे सिपाही फिर अपनी पहले की जगह पर पहुंच गये थे । यह सब लगभग दो मील के क्षेत्र के सवाल पर किया गया था । हमारा ख्याल है कि वहां एक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है; उसके दो मील इस तरफ को पुल है, और दो मील उस तरफ हमारी एक छोटी सी टुकड़ी चौकसी के लिये रहती है । इस तरह हमारे गश्ती दस्ते को पुल तक ढकेल दिया गया था और दो मील दूर दोनों तरफ के सिपाही एक-दूसरे के आमने सामने खड़े थे । उसके बाद दोनों ही वहां से हट गये । मैं अभी तक ठीक से नहीं समझ पाया हूं कि ऐसा क्यों किया गया था । वहां शायद कोई एक पहाड़ है । शायद रात के वक्त फौजें वापस चली गई थीं । जो भी हो, बाद में चीनी टुकड़ी पीछे हट गई थी और हमारा गश्ती दस्ता अपनी पहले की जगह पर फिर से पहुंच गया और वहां एक छोटी सी चौकी स्थापित करा दी । कुछ अर्से के बाद चीनी टुकड़ी फिर वहां आ गई और उस ने हमारे दस्ते से उसी दम पीछे हट जाने और अपना झंडा झुका देने के लिये कहा । हमारे सिपाहियों ने इस से इन्कार कर दिया । चीन की फौजों ने इस के बाद हमारे दस्ते को घेरने की कोशिश की, लेकिन जहां तक हमें मालूम है हमारे जवान अपनी जगह पर ही अड़े रहे, यानी सीमा पर जमे रहे । उस सीमा पर इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ । यह सब करीब दो हफ्ते पहले हुआ था ।

अब जो मैं इस दूसरी घटना की बात बता रहा हूं वह बहुत हाल की है और असल में पहले से ही चली आ रही है । २५ अगस्त को, यानी तीन दिन पहले, चीन की एक काफी बड़ी फौजी टुकड़ी सुबिनसिरी फ्रंटियर डिवीजन में मिग्यियन के दक्षिण में एक स्थान पर हमारे इलाके में घुस आई और उस ने गोली चलानी शुरू कर दी । माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैं ने अभी-अभी मिग्यियन का जिक्र किया था । चीन सरकार ने इसी जगह के बारे में शिकायत की थी कि हमारी फौजों ने उनके इलाके में प्रवेश किया था और तिब्बत के बागियों से कुछ साठ गांठ की थी । वह शिकायत जून में की गई थी और मामला वहीं खत्म भी हो गया था । अब इस बार उसी इलाके के आसपास, उससे थोड़ी ही दूरी पर, ज्यादा दूरी पर नहीं, चीन की फौजी टुकड़ी हमारे इलाके में घुस आई और ऐसा कहा जाता है कि उस ने हमारे आगे के गश्ती दस्ते के करीब एक दर्जन लोगों पर गोली चलाने लगी । चीनियों की तादाद बहुत ज्यादा थी । कितनी थी यह तो बताना मुश्किल है पर वे २००-३०० या इससे कुछ ज्यादा तादाद में थे । उस टुकड़ी ने हमारे गश्ती दस्ते के बारह सिपाहियों को घेर लिया । गश्ती दस्ते में 'आसाम राइफिल्स' का १ एन० सी० ओ० और ११ राइफिलमैन थे । उन बारहों को हिरासत में ले लिया गया । बाद में उन ११ राइफिल मैनों में ८ बचकर निकल आये । वे हमारी चौकी पर आ गये । हमारी चौकी लोन्गजू में है । जैसा हमारा ख्याल है लोन्गजू तिब्बत और भारत की हमारी सीमा से करीब ३-४ मील की दूरी पर है । उससे कुछ बड़ी हमारी चौकी सीमा में अन्दर की ओर लिमेकिंग में है । उससे लोन्गजू तक पैदल जाने में पांच दिन लगते हैं । उससे बाद की चौकी तक पैदल आने में लिमेकिंग से १२ दिन लगते हैं । इस हिसाब से, लोन्गजू से मुख्य सड़क तक पैदल आने में करीब तीन हफ्ते लग जाते हैं । मैं यह सारा ब्यौरा सिर्फ इसलिये बता रहा हूं कि आपको पता लग जाये कि उस इलाके में कितनी बड़ी बड़ी दूरियां हैं और उनको तय करने में कितना वक्त लग जाता है । मैं बता रहा था कि २५ अगस्त के दिन चीन की फौजी टुकड़ी ने हमारे आगे के

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इस गश्ती दस्ते को गिरफ्तार कर लिया था, उन में से आठ बच कर निकल भागे थे और दूसरे दिन २६ को वापस आ गये थे। चीनी टुकड़ी बाद में फिर आई और उस ने गोली चलाई। उस ने हमारी चौकी और गश्ती दस्ते को घेर लिया। सच तो यह है कि उहोंने इस लोंगजू की चौकी को घेर लिया था। काफी देर तक गोली चलने के बावजूद किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली है। लोन्गजू की चौकी घिर जाने के बाद, चौकी के लोगों ने वह जगह छोड़ दी और फौजियों के बहुत ज्यादा दबाव के सामने पीछे हट आये। यह सब परसों शाम को हुआ था। इसलिये अभी तक हमें उसकी बिलकुल ठीक-ठीक जानकारी नहीं हो पाई है।

हमें जैसे ही यह खबर मिली, तो हम ने उसी दम चीन सरकार से इसके बारे में शिकायत की। साथ ही हम ने वहां की अपनी कई चौकियों को और मजबूत बनाने के लिये, मिसेमिंग वगैरह चौकियों की ताकत बढ़ाने के लिये कुछ जरूरी कदम भी उठायें। असल में हमने नेफा के इस सारे सीमान्त क्षेत्र को अपने सैनिक अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया है। मतलब यह है पहले वहां 'आसाम राइफिल्स् डायरेक्टोरेट' के अधीन 'आसाम राइफिल्स्' का पुलिस बल तैनात था, और 'आसाम राइफिल्स् डायरेक्टोरेट' राज्यपाल की अधीनता में था और राज्यपाल वैदेशिक कार्य मंत्रालय में भारत सरकार के एक अभिकर्ता के रूप में काम करता था। आसाम राइफिल्स्' के सिपाही तो अभी भी उस इलाके में रहेंगे, और वहां जरूरत पड़ने पर और भी सिपाही भेजे जायेंगे, लेकिन अब उन सभी को फौजी अधिकारियों और उनके प्रधान कार्यालय की अधीनता में चलना पड़ेगा।

इस सब को करने में कुछ समय तो लग ही गया है। मैं आपको बता चुका हूं कि वहां तक आने जाने में हफ्तों लग जाते हैं। लोन्गजू में हमारा एक गश्ती दस्ता रहता है जिस में शायद कुल मिला कर ३८ लोग हैं। शायद उस दस्ते को हथियारों की कमी पड़ गई थी, क्योंकि वहां हथियार पहुंच ही नहीं रहे थे। हम ने हवाई जहाजों के जरिये हथियार पहुंचाने की कोशिश की थी। वहां हथियार गिराये भी गये थे लेकिन उन को मिल नहीं सके। वह एक पहाड़ी इलाका है और वहां हथियार पहुंचाना आसान भी नहीं है। यहां से छतरीधारी सैनिकों को वहां पहुंचाना भी काफी खतरनाक है। इसलिये हम ने उसे ठीक नहीं समझा। जो भी हो, वहां जो भी कुछ किया जा सकता था, हम ने किया है।

अभी मुझे पीकिंग के अपने राजदूत से एक संदेश मिला है। उन्होंने जब यह नोट चीन के अधिकारियों को दिया था, तो उनका जवाब था कि उनकी अपनी सूचना दूसरे ही ढंग की थी। पीकिंग में डायरेक्टर का कहना है कि चीन सरकार को जो सूचना मिली है वह हमारे एक प्रतिनिधि कन्नम्पिल्ली को दिये गये नोट में शामिल है। मिग्यितुन के बारे में, उनकी रिपोर्ट यह है कि वहां भारतीयों ने ही पहले गोली चलाई थी और चीन के सीमान्त सैनिकों ने उसी के जवाब में गोली चलाई थी। २६ अगस्त को लोंगजू में होने वाली मुठभेड़ के बारे में अभी तक उनके पास कोई सूचना नहीं पहुंची है। चीन की ओर से यही जवाब दिया गया है। उनके डायरेक्टर का कहना है कि इस इलाक़े में तनातनी इसीलिये है कि भारतीय सेनायें लगातार आगे बढ़ रही हैं। ठीक इसी तरह के जवाब में पाकिस्तान से मिलते हैं। ठीक वही भाषा है। हम जब किसी घटना का ब्यौरा उनके पास भेजते हैं, तो दूसरी तरफ़ से उसका ठीक उल्टा ब्यौरा भेज दिया जाता है कि गोली चलाना हमने शुरू किया था।

मैं मानता हूं कि इन मामलों में मैं अपनी ही रिपोर्टों को सही मानता हूं। मेरा यकीन है कि वे सच हैं, क्योंकि मैं उस इलाक़े के अपने ही लोगों की बात सही मानता हूं। वे लोग काफी काम सीखे हुए, तजुर्बेकार लोग हैं और नमक मिर्च लगाने के आदी नहीं हैं। और, फिर वहां की जो हालत है उसे देखते हुए भी उनकी रिपोर्ट ही सही मालूम पड़ती है। हमारे राजदूत ने चीन के अधिकारियों के सामने यही बात रखी थी। मैं यह नहीं चाहता कि इस परिस्थिति को देख कर हम भड़क उठे; यह घटनायें

अपने आप में तो बड़ी छोटी मोटी ही हैं। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि इन छोटी-मोटी घटनाओं के पीछे है क्या। जो भी हो हमें सतर्क रहना चाहिये और अपने सीमांत की रक्षा भरसक करनी चाहिये।

†**श्री गोरे :** प्रधान मन्त्री ने कहा है कि लद्दाख, भूतान, सिक्किम और नेफा के ये स्थान एक-दूसरे से सैकड़ों मील दूर हैं। सही है, लेकिन वहां घटने वाली घटनाओं के पीछे हाथ तो एक ही मालूम पड़ता है। इसलिये सवाल यह है कि चीन सरकार की नीति हमारे देश के बारे में क्या है ? यदि भारत अपने सीमान्त की रक्षा नहीं कर सकेगा, तो फिर चीन बरमा और इण्डोनेशिया पर भी चढ़ बैठेगा। इसीलिये मैं चाहता था कि इसके बारे में पूरी तौर से चर्चा की जाये।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : क्या इन सब घटनाओं का यही मतलब है कि चीन अपने तैयार किये हुए नक्शों के आधार पर ही अपनी सीमा निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है ? मैं तो यही समझता हूं।

†**श्री बि० दास गुप्त** (पुरुलिया) : क्या चीन सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा गया है कि दोनों देशों की सरकारें आपस में बैठ कर इस मसले पर बातचीत करें ?

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहस-राम) : प्रधान मत्री का कहना है कि इस चौकी पर छतरीधारी सैनिकों को उतारना मुश्किल है। क्या चीनी फौजों से उस क्षेत्र को छीनने के लिये वहां बम वर्षा करना सम्भव है ?

†**श्री हेम बरुआ :** क्या नेफा में चीनियों के इस अनधिकार प्रवेश का कारण चीन सरकार द्वारा तैयार किये गये नक्शों की ग़लती है, जिसके बारे में हमने चीन सरकार से शिकायत की थी और उसने कहा था कि वे नक्शे च्यांग-काई शेक के शासन-काल में बने थे ?

†**पंडित गोविन्द मालवीय** (सुलतानपुर): प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि इस समस्या के बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या है। हालत बड़ी नाजुक है, क्योंकि चीन हमारा मित्र देश है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी व्यौरेवार चर्चा से कोई लाभ नहीं होगा। हमें यह बड़े बड़े सवाल सरकार पर ही छोड़ देने चाहियें। आन्तरिक मामलों पर हमारी नीतियों में मतभेद हो सकता है, वैदेशिक मामलों पर नहीं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जहां तक और बड़ी-बड़ी नीतियों का ताल्लुक है, वे तो हमारे सामने हैं। लेकिन अभी तो हमें एक खास परिस्थिति कामुकाबला करना है। और ऐसी परिस्थिति जिस भी देश के सामने खड़ी होगी, उसे उसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। अपने मुल्क की सीमा की रक्षा करने के अलावा, हमारे सामने कोई और चारा ही नहीं रह गया है। लेकिन यह भी जरूरी है कि, जैसा अक्सर ऐसी हालत में होता है, हमें बे वजह भड़क भी नहीं उठना चाहिये, डरना भी नहीं चाहिये और कोई ग़लत कदम नहीं उठाना चाहिये।

मैंने आपके सामने सारी जानकारी रख दी है। पहले की भी, और बिल्कुल हाल की भी। मैंने आपको वह तार भी बता दिया है, जो मुझे यहीं सभा में अभी-अभी मिला है। हमारे राजदूत ने इस तार में अन्य बातों के अलावा यह कहा है :

> "मैंने उन्हें बताया कि २५ और २६ अगस्त की घटनाओं के फलस्वरूप हमारे चार आदमियों"—असल में तीन आदमियों—" का अभी तक कोई भी पता नहीं चला है : चीनी फौजों ने लोंगजू पर हमला किया था, जो चीनी भली भांति जानते हैं कि भार-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

तीय क्षेत्र में स्थित है। मैंने चीनी सरकार के सामने अपनी सरकार की इच्छा फिर से दोहराई कि उसे जोर-जबर्दस्ती के बल पर हअपने दावों को पेश न होने देने के लिये कदम उठाने चाहिये। मतभेदों का निवटारा बातचीत के जरिये ही किया जाना चाहिये।"

हम इसी नीति पर चल रहे हैं कि सीमांत पर होने वाली छोटी मोटी घटनाओं और सीमा सम्बन्धी मत भेदों को आपसी बातचीत के जरिये ही निबटाना चाहिये। हमें इन छोटी-मोटी घटनाओं और मुठभेड़ों के सवाल को चीनी नक्शों के बड़े सवाल से अलग रख कर देखना चाहिये। दोनों सवाल अलग-अलग हैं। चीनियों ने अपने नक्शों में कई मील के भारतीय इलाकों को चीन के हिस्से की तरह रंग कर दिखाया है। जाहिर है, इसे हम कतई नहीं मान सकते और हमने उनसे साफ़ साफ़ कह भी दिया है। हम सीमा के मामले में लाइन को ही मानते हैं। यह तो एक बड़ा सवाल है। हां, यह दूसरी बात है कि इस इतनी लम्बाई-चौड़ाई में कहीं कहीं एक मील इधर या उधर रखने के बारे में कुछ मतभेद हो सकता है। चीन के तिब्बत में आने से पहले भी इस किस्म की बातें चल रही थीं। तिब्बत के अधिकारियों के साथ भी एकाध मील के बारे में ऐसा हो चुका है। इस सम्बन्ध में अभी भी दोनों में कुछ मतभेद मौजूद हैं जिनका निबटारा किया जाना चाहिये। हम समझते हैं कि हमारा दावा ही ठीक है, लेकिन हम उसके निबटारे के लिये बातचीत करने को तैयार हैं। हम ऐसे हर एक मामले के बारे में बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन जहां बड़े-बड़े इलाकों का सवाल है, वहां बहस करने और बातचीत करने की कोई गुंजाइश ही नहीं।

मैंने आपके सामने जो एक-दो उदाहरण रखे हैं, उनसे जाहिर हो जाता है कि चीनियों ने हमारे क्षेत्र में अनधिकारि प्रवेश किया है। लेकिन अगर तिब्बत या चीन एक दो-मील के किसी इलाके को अपना समझते हैं, तो हम उसके बारे में बैठ कर बातचीत करने के लिये तैयार हैं। लेकिन जैसा कि इन उदाहरणों से जाहिर है, चीन की फौजों ने हमारी चौकी को घेरा है सिपाहियों को पकड़ लिया है और गोली चलाई है। इसे कम से कम शान्तिपूर्ण तरीका तो नहीं कहा जा सकता। अगर कोई विवाद है भी, तो उसे हल करने का, निबटाने का यह तो कोई ठीक तरीका नहीं है। इसीलिये यह मामला छोटी-मोटी घटनाओं का नहीं रह गया है, आम तौर पर होने वाली मुठभेड़ों का मामला नहीं रह गया है। यह उससे कहीं ज्यादा गम्भीर मामला बन गया है।

श्री खाडिलकर या शायद किसी और माननीय सदस्यने पूछा है कि इन सब घटनाओं के पीछे कौनसी चीज है। मैं नहीं बता सकता। इस मामले में कोई अच्छा अन्दाज लगाना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह तो सिर्फ़ अन्दाज ही होगा। लेकिन मैं यह कतई नहीं सोचता कि यह सब घटनायें किसी और बड़ी गम्भीर चीज़ की भूमिका है। मैं तो समझता हूं कि अगर कोई भी सरकार ऐसा सोच कर भूमिका के रूप में ऐसी घटनायें करायें, तो यह उसकी बड़ी हिमाकत ही होगी। चीन सरकार भी अगर इस तरह काम करे तो, यह उसकी हिमाकत ही मानी जायेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि चीन सरकार ऐसी हिमाकत नहीं कर सकती। इसीलिये मेरा ख्याल है कि चीन सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन जहां तक हमारा अपना ताल्लुक है, जाहिर है हमें तो हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये तैयार ही रहना चाहिये, बिना किसी चीख-पुकार के हमें सतर्क रहना ही चाहिये।

शायद डा० राम सुभग सिंह ने मुझे और सेना को कुछ सलाह दी थी, कि उन्हें कैसे काम करना चाहिये, क्या करना और क्या न करना चाहिये, और हवाई जहाज़ों से वहां उतरना चाहिये। इन बातों पर सेना को ही विचार करना पड़ेगा। कहां कौनसी चीज़ मुमकिन या नामुमकिन है इसका फैसला सेना ही करेगी, हम नहीं।

एक माननीय सदस्य का सुझाव था कि इस मामले पर चर्चा की जाये। मैं हमेशा सभा में चर्चा करने के पक्ष में रहता हूं, लेकिन मेरी राय में इसके बारे में चर्चा करने से कोई भी लाभ नहीं होगा। यदि कोई और नयी घटनायें होंगी तो मैं उनका ब्यौरा सभा के सामने रखता रहूंगा और अगर हमें कोई कदम भी उठाना पड़ा तो उसे भी सभा के सामने लाया जायेगा।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर): मेरा सुझाव है कि सरकार को इन सभी घटनाओं का ब्यौरा, चीन के साथ हमारे सीमा सम्बन्धी विवाद और इस हमले का पूरा विवरण एक श्वेत-पत्र में सम्मिलित करना चाहिये, जिससे कि विश्व के जनमत को उनकी पूरी जानकारी हो सके।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं इस सुझाव पर गौर करने के लिये तैयार हूं। ऐसा श्वेत पत्र जारी करने में कुछ समय लग जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय प्रधान मन्त्री के इस ब्यौरे वार वक्तव्य के बाद, मैं समझता हूं कि इन स्थगन प्रस्तावों को चर्चा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। मैं उनकी अनुमति नहीं देता।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश): श्रीमान्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है, मैंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों के कार्यों के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं ने उस की अनुमति नहीं दी है।

†**श्री शि० ला० सक्सेना**: आप ने कहा है कि यह एक स्वायत्तशासी संस्था के कार्यों के सम्बन्ध में है। मैं जानना चाहता हूं क्या सभा उस के मामलों पर चर्चा इसलिये नहीं कर सकती क्योंकि वह एक स्वायत्तशासी संस्था है।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अनुशासन संबंधी कार्यों के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में औचित्य प्रश्न उठाया है। मैं बताना चाहता हूं कि इस के प्रशासन के बारे में हम एक विधान पारित कर चुके हैं और फैसला कर चुके हैं कि एक विशेष समिति इस का प्रबन्ध करेगी। दिन प्रति दिन के प्रशासन के बारे में यहां मामले उठाने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं नहीं चाहता कि इउ सभा में चर्चा कर के हम वहां प्रबन्ध करने वालों के काम में रोड़े अटकायें। अतः मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं देता हूं।

ज्यूं ही किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है, इस सभा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के खिलाफ अपील सुनने के लिये हम यहां नहीं बैठे हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वह यहां पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर के उस संस्था का प्रशासन करने वालों के काम में बाधा उत्पन्न न करें। यदि हम इस तरह से मामले उठाते रहें तो वहां के लोगों को अनुचित प्रोत्साहन मिलेगा और वे हर बात के लिये संसद्-सदस्यों के पास पहुंच जायेंगे और इस प्रकार प्रबन्धकों के काम में बाधा डालेंगे। यह एक बहुत गलत बात है। इस तरह से कोई स्वायत्तशासी संस्था काम नहीं कर सकती।

मैं यह भी इस सभा में दोबारा बता देना चाहता हूं कि एक बार जब मैं किसी स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं देता हूं तो उस को यहां पर नहीं उठाया जाना चाहिये। इस का भी अनुचित प्रभाव पड़ता है। मैं इस बात को सभा में बार बार बता चुका हूं। परन्तु मुझे खेद है कि फिर भी श्री शि०

---

†मूल अंग्रेजी में